eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

भारत की शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

डा0 शिप्रा वर्मा[1], दीप्ती कटियार[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनौगी, कन्नौज उ0प्र0

[2]शोध छात्रा, डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनौगी, कन्नौज उ0प्र0

Received: 15 April 2025 Accepted & Reviewed: 25 April 2025, Published: 30 April 2025

Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभारी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, जो छात्रो के समग्र विकास पर जोर देती है। इस नीति की संरचना 10़2 के स्थान पर 5़3़3़4 लागू की गई है। यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे शैक्षणिक ढांचे का निर्माण करती है जो प्रत्येक छात्र के हितो और आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सर्वसुलभ भी है। छम्च 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन को 2035 तक 26% से बढाकर 50% करना है। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंटी और एडिजट सिस्टम और व्यवसायिक शिक्षा को बढावा दिया गया है। शोध और नवाचार को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउन्डेशन की स्थापना की जायेगी।

छम्च 2020 त्रिभाषा नीति को सीखने पर बल देती है। यह नीति राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान में हिन्दी के महत्व को मान्यता देती है और हिन्दी के विकास और प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नीति का मुख्य उददेश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरुप बनाकर छात्रो को भविष्य के लिए तैयार कना है।

मुख्य शब्द– नई शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा, डिजिटल युग, कौशल विकास।

Introduction

किसी भी देश की समृद्धि और विकास का आधार शिक्षा है। देश की शिक्षा प्रणाली से उसके नागरिको का सर्वागीण विकास हो सकता है। भारत देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्दिरा गांधी सरकार ने सन 1968 में घोषित की थी। यह नीति दौलत सिंह कोठरी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी। इस नीति के जरिए देश में शिक्षा सुधारो और विकास की नीव रखी गयी। यह नीति 14 वर्ष के बच्चो के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक और योग्यता, तीन भाषा फार्मूला सभी को शिक्षा का समान अवसर और 10+2+3 संरचना पर केन्द्रित थी। देश की दूसरी शिक्षा नीति सन 1986 में लागू की गयी, इस नीति का उद्देश्य असमानताओ को दूर करने विशेष रुप से भारतीय महिलाओ, अनुसूचित जनजातियो और अनुसूचित जाति समुदायो के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलो को बेहतर बनाने के लिए ''आपरेशन ब्लैकबोर्ड'' लांच किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ''ओपन यूनीवर्सिटी'' प्रणाली का विस्तार किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है। यह नीति शिक्षा में पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य तथा जवाबदेही पर केन्द्रित है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी को आवश्यकताओं के अनुरुप बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। ''भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतापूर्ण और जीवंतज्ञान समाज में बदलने में सीधे योग देती है, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है।''

यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा को प्रभावित करती है। इस नीति में छात्रों को मनपसंद शिक्षा देकर उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बल देती है। इसका उद्देश्य शिक्षा को छात्र केन्द्रित बनाना, रटने की प्रणाली को खत्म करना और कौशल विकास पर जोर देना है।

अध्ययन के उददेश्य–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा प्रणाली को समझना और जानना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना की जानकारी देना।
3. उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पहचानना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिन्दी के महत्व को जानना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषतायें–

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली में वियापक सुधार किये गये है। इसकी विशेषतायें इस प्रकार हैः–

- शिक्षा की संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू की गई है जिसमें फाउन्डेशन प्रियरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज शामिल है।
- बहुप्रवेश और बहुनिर्गमः उच्च शिक्षा में छात्रों को अपनी पढाई के दौरान कई बार प्रवेश और निकास का विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी शिक्षा को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकेगें।
- NEP 2020 के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओ को दूर करने, दिव्यांग छात्रो के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढावा देने पर बल दिया गया है।
- इस नीति में छात्रो में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
- यह नीति शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं जिसमें इसका विनियमन प्रशासन भी शामिल है के पुनपरीक्षण और पुनुरुद्धार का प्रस्ताव करती है, ताकि एक नई प्रणाली बनाई जा सके जो भारत की परम्पराओं और मूल्य प्रणालियो पर आधारित सतत विकास लक्ष्य सहित 21वी सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यो के साथ संरचित हो।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

- उच्च शिक्षा में व्यवसायिक और कौशल आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिससे छात्रो को इन्टर्नशिप और इन्डस्ट्री से जुडे प्रोडक्टस करने के अवसर मिलेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना–

NEP 2020 की संरचना शिक्षा प्रणाली के संचालन के तरीके को महत्वपूर्ण रुप से बदलाव करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले 10+2 मॉडल की जगह नई 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली पेश की है। यह नई प्रणाली शैक्षणिक संरचना को 4 अलग–अलग चरणो में विभाजित करती है।

आधारभूत चरण (5 वर्ष)

यह शिक्षा का पहला चरण 5 वर्षो का है जो 3 से 8 वर्ष की आयु के छात्रो पर केन्द्रित है 3 वर्ष प्री–प्राइमरी और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 शामिल है। बच्चो की शिक्षा के प्रारम्भिक शिक्षा खेल खेल में शिक्षा प्रदान और आवश्यक सामाजिक संपर्क और स्थानीय भाषा विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

प्रारम्भिक चरण (3 वर्ष)

यह शिक्षा का दूसरा चरण 3 वर्षो का है जो 8 से 11 वर्ष की आयु के छात्रो पर केन्द्रित है। इसमें कक्षा 3 से 5 तक को शामिल किया गया है छात्रो को मूलभूत विषयों और गतिविधियो से परिचित कराया जायेगा तथा शिक्षा मातृभाषा में ही प्रदान की जायेगी।

मध्य चरण (3 वर्ष)

इस चरण में 3 वर्ष की शिक्षा 11 से 14 वर्ष के आयु के बालको के लिए है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाये शामिल है। इस चरण में छात्रो को विषयो की गहन समझ को विकसित करने की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

माध्यमिक चरण (4 वर्ष)

यह शिक्षा का अंतिम चरण 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए 14 से 18 वर्ष की आयु के छात्रो के लिए है।

यह शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित है। यह छात्रो का समग्र मूल्याकंन कर उनकी समस्याओ का भी समाधान करती है यह प्रणाली छात्रो को मनपसंद शिक्षा देकर उनका कौशल विकास करती है। यह शिक्षा प्रणाली पुरानी प्रणाली से अत्यधिक उन्नत, रोचक, आकर्षक और समवर्धक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वन–

इस शिक्षा नीति का उद्देश्य समता और समानता को बढावा देना है। जहाँ पहले की शिक्षा नीति 1968 और 1986 का उददेश्य शैक्षिक ढांचे मे सुधार पर आधारित थी और शैक्षिक असमानताओं का उन्मूलन चिंता के केन्द्र में था। वही नई शिक्षा नीति 2020 अधुनातन शैक्षिक साधनों और नवोन्मेष के माध्यम से समानता और समावेशन को बढावा देती है। यह नीति ऐसे शैक्षणिक ढांचे का निर्माण करती है जो प्रत्येक छात्र के हितो आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए सर्वसुलभ भी है। इस नीति में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन विशेषकर मातृभाषा में भारतीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम किया को संचालित किया जा रहा है

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

और पाठ्य सामग्री हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं मे तैयार की जा रही है। शिक्षको को निरन्तर प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्ति और प्रोन्नति की जा रही है। व्यवसायिक शिक्षा के लिए नए व्यवसायिक संस्थान खोलने पर विशेष बल दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ और मुक्त शिक्षा को बढावा देते हुए सकल नामांकन को निरन्तर बढाया जा रहा है। NEP 2020 लागू होने के परिणाम स्वरुप समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे है। जैसे अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। छात्र त्रिवर्षीय आनर्स प्रोग्राम या चतुवर्षीय आनर्स प्रोग्राम का चयन कर रहे है। भारत सरकार शिक्षा के माध्यम के साथ–साथ भारतीय मातृभाषा कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दे रही है। राष्ट्रीय नीति इसे संभव कर रही है। रही है। इसके अन्तर्गत कई उच्च शिक्षण संस्थान क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के साथ साथ स्थानीय भाषा को शिक्षण का माध्यम बना रहे है।

सभी वर्गो को समान अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, विशेष ऋण छात्रवृत्तियो और पुरस्कार आदि सुनिश्चित किए गए है शिक्षको की शिक्षण विधियाँ प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश के विभिन्न विद्यालयो ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप पाठयक्रम में आधाभूत परिवर्तन और विषय चयन में लचीलापन, बहुविषयमता, गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार, कालेज की स्वायत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण आदि को अपनाया है। विश्वविद्यालयो मे इन्नोवेशन सेन्टर, इन्क्यूवेशन सेन्टर, स्टार्ट अप फन्ड, उद्यमोदय फाउन्डेशन, विश्वविद्यालय फाउन्डेशन और रिसर्च पार्क आदि की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

NEP 2020 का उच्च शिक्षा में प्रभाव–

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 26% से बढाकर 50% करना है। 1 नई शिक्षा नीति कई बदलावा लाने के तैयार है जिसमे विदेशी विश्वविद्यालयो को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देना, छात्रो को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना और आईआईटी सहित संस्थानो को बहुविषयक बनाना शामिल है।

नीति का उद्देश्य भारतीयो मे ज्ञान, कौशल, मूल्य विकसित करना है जो मानवाधिकारो, सतत विकास और जीवन और वैश्विक कल्याण के प्रति जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करते है।

उच्च शिक्षा के पूरे क्षेत्र के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जायेगी। 1 संस्थानो को समय के साथ समाप्त कर दिया जायेगा और सभी बहुविषयक बनने की दिशा में आगे बढेंगे। संबद्ध कालेजो की प्रणाली को 15 वर्षो मे धीरे धीरे समाप्त किया जायेगा। विश्वविद्यालय को बहुविषयक संस्थान जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुडाव के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना है। इस प्रकार शिक्षण और अनुसंधान पर समान जोर देने वाले संस्थानो से लेकर शिक्षण गहन विश्वविद्यालयो तक के संस्थानो की एक श्रंखला शामिल होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिन्दी –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किये है जिसमे से एक है त्रिभाषा नीति यह नीति तीन भाषाओं को सीखने पर जोर देती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अग्रेजी पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रजी के साथ हिन्दी को शामिल करके NEP 2020 राष्ट्रीय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

एकीकरण और सांस्कृति आदान प्रदान में हिन्दी के महत्व को मान्यता देती है। हिन्दी सीखने से भारत भर के छात्रो को न केवल व्यापक दृष्टिकोण से जुडने में मदद मिलेगी बल्कि देश की विरासत, साहित्य और मूल्यो के बारे में गहरी जानकारी भी मिलती हिन्दी अक्सर शैक्षणिक संस्थानो में अंग्रेजो से प्रतिस्पर्दा करने में संघर्ष करती है। शिक्षा के माध्यम मे अंग्रंजो को प्राथमिकता देना हिन्दी भाषी छात्रो के लिए बाधा उत्पन्न करती है। शैक्षणिक सस्थानों को हिन्दी पाठयक्रम शामिल करके अवसर की भाषा के रुप मे बढावा देना चाहिए। यह नीति हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिससे हिन्दी भाषी क्षेत्र के बच्चो को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने मे मदद मिलती है।

NEP 2020 की चुनौतियाँ –

शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यो के अपने स्कूल बोर्ड है। इसलिए इसमें क्रियान्वन हेतु राज्य सरकार को अपने स्तर पर प्रयास करने होगें विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होना एक चुनौती है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षणो का अभाव है ऐसे NEP 2020 की प्रारम्भिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वन मे व्यवहारिक समस्याये भी है। इस नीति के कार्यान्वन में सबसे बडी बाधा आर्थिक संसाधन और सुविधाओ का अभाव है। सरकार को शिक्षा में निवेश बढावा होगा ऐसा करके ही भारत को विश्वगुरु और विश्वशक्ति बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि 21वीं सदी भारत की जरुरतो को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली मे बदलाव हेतु नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। अगर उसका क्रियान्वन सफल तरीके से होता है तो भारत को अग्रणी देशो को समक्ष ले जायेगी नई शिक्षा नीति 2020 मे 3 से 18 वर्ष तक के बच्चो को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। उपवर्गो पश्चात इस नीति का उददेश्य सभी छात्रो का उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आर्टिफिशियल इटेलीजेन्स, थ्री डी मशीन डेटा विश्लेषण जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रो के समावेशन मे अत्याधुनिक क्षेत्रो मे भी कुशल पेशेवर तैयार होगे और युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा।

संन्दर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए एनईपी की मुख्य बिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स
3. के पीएम जी रिपोर्ट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव और हितधारको के लिए अवसर, अगस्त 2020
4. अग्रवाल, पवन, श्रम बाजार के अनुरुप उच्च शिक्षा योजनाअंक 9 सितम्बर 2009 पृष्ठ सं0 11–13
5. चौरसिया, मुकेश, भारत मे उच्च शिक्षा : समस्याये एंव समाधान योजना अंक 9 सिंतम्बर 2009 पृष्ठ सं0 27– 30
6. अरुज, चित्रा 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली : शिक्षा के नये युग को समझना, senseseles.com, 8 मार्च 2025
7- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वन, अनुसंधान की दिशा में बढा कदम, My Gov Blog, 7 Feb 2024

8. भारतीय शिक्षा में हिन्दी भाषा का महत्व, lead shoolim, 16-09-2024
9. नई शिक्षा नीति 2020, दृष्टि, 25 Aug 2020
10. www.google.com
11. नई शिक्षा नीति 2020 wikipedia 04-01-2021
12. www.wikipedia.com
13. http//www.dristhias.com